



ब्रिटेन की महारानी क्वीन ऐलिजाबैथ की गुरुवार दोपहर को मृत्यु हो गई। वे 96 वर्ष की थीं। बर्किंगहम पैलेस की ओर से जारी बयान के अनुसार वे लम्बे समय से उम्र से जुड़ी बीमारियों एवं समस्याओं से ग्रसित थीं। डॉक्टरों ने उनके स्वास्थ्य के बारे में बुधवार को जारी बुलेटिन में बताया था कि, उनकी हालात काफी गम्भीर हैं। क्वीन ऐलिजाबैथ ने ब्रिटेन पर 70 वर्षों तक शासन किया। स्कॉटिश एस्टेट बालमोरल में उनके खराब स्वास्थ्य को देखते हुए सारा परिवार इकट्ठा था। उनके पुत्र प्रिंस चार्ल्स अपनी पत्नी कमिला तथा पुत्र और पुत्रवधुओं व पोते-पोतियों के साथ बालमोरल पहुँच गए थे। क्वीन ऐलिजाबैथ काफी समय से बीमार थीं पर, राज परिवार की ओर से ज्यादा जानकारी नहीं दी गई, क्योंकि ब्रिटेन राज परिवार स्वास्थ्य को बेहद निजी मुद्दा मानता है।

## नेताजी को 75 साल इंतजार करना पड़ा अपना उपयुक्त व उचित स्थान पाने के लिये

इस मौके पर प. बंगाल की ममता बनर्जी का समारोह का “बॉयकाट” करना कुछ ओछा ही लगा

—अंजन राय—  
—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—  
नई दिल्ली, 8 सितम्बर नेताजी सुभाष चन्द्र बोस को देश की आजादी की लड़ाई में अपने योगदान को राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित करवाने के लिए पूरे 75 साल इंतजार करना पड़ा।  
इस पर भी नेताजी के गृह राज्य बंगाल की वर्तमान सरकार ओछे बहाने बना कर इस कार्यक्रम से दूर हो गई है और बंगाल को इसमें शामिल नहीं होने दे रह है।  
सम्मान के इस क्षण में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राजनैतिक कार्ड खेला है ताकि केन्द्र में सत्तारूढ पार्टी को इस अवसर का राजनैतिक लाभ न मिल सके।  
इसे बेहद ओछी हरकत माना जा सकता है। देश की राजधानी में हो रहे प्रतिभा अनावरण कार्यक्रम को कमतर करने के लिए ममता बनर्जी के कोलकाता में एक कार्यक्रम और बोस की मूर्ति पर माल्यार्पण किया।  
उन्होंने यह कदम इसलिए उठाया कि कहीं दिल्ली के कार्यक्रम में शामिल नहीं होने से बंगाल की जनता को बुरा न लगे। इससे कोई इन्कार नहीं है कि दिल्ली के कार्यक्रम पर उनकी प्रतिक्रिया असल में देश की आजादी के में बोस के योगदान व महत्व को उभारने के प्रयासों का अपमान है।

सी.ए.ए. पर सुनवाई  
—जाल खंबाता—  
—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—  
नई दिल्ली, 8 सितम्बर चीफ जस्टिस ऑफ इण्डिया (सी.जे.आई.) उदय उमेश ललित और जस्टिस रविन्द्र भट की दो जजों वाली बैंच सिटीजनशिप (अमेण्डमेंट) एक्ट 2019 (सी.ए.ए.) को चुनौती देने वाली 2 सी से अधिक याचिकाओं पर सोमवार को

■ सुप्रीम कोर्ट में सी.ए.ए. को चुनौती देने वाली दो सौ याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई होगी, ये याचिकाएं जनवरी 2020 से लम्बित हैं।  
सुनवाई करेगी। सी.ए.ए. का उद्देश्य पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के प्रवासी लोगों को भारत की नागरिकता देना था। याचिकाएं तभी से सुप्रीम कोर्ट के (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

■ बंगाल में यह भावना काफी गहरी थी कि, स्वतंत्रता आंदोलन का श्रेय नेहरू-गांधी द्वय को ही मिला तथा सुभाष चन्द्र बोस की स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका सदा दबायी गयी। अब जब यह अन्याय दुरुस्त हो रहा था, तो छोटी सी बात पर समारोह का बहिष्कार करना बंगाल की जनता को खलेगा, यह सोच कर ही ममता बनर्जी ने एक दिन पूर्व नेताजी की मूर्ति को माला पहनाकर, जनता को कुछ संतोष दिलाने की कोशिश की।  
■ प. बंगाल की कम्युनिस्ट पार्टी प्रारंभ से ही, सुभाष बाबू द्वारा जापान व हिटलर की जर्मनी से स्वतंत्रता संग्राम में मदद लेने की आलोचना करती आयी है, परन्तु सोवियत रूस द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के शुरूआती दौर में हिटलर की जर्मनी से गठबंधन करने को, कम्युनिस्ट पार्टियाँ युद्ध की रणनीति का हिस्सा बताकर जायज ठहराती आयीं, पर उनका विरोध किसी राजनीतिक सिद्धांत पर आधारित था, न कि, छोटी-मोटी “प्रोटोकॉल” की चूक पर।

आजादी के बाद से ही बंगाल का यह सोच रहा है कि सुभाष चन्द्र बोस को उनके योगदान तथा बलिदान के लिए यथेष्ट राष्ट्रीय सम्मान नहीं मिला। नेहरू गांधी परिवार के खिलाफ बंगाल में कड़ी जन भावना है। ममता बनर्जी का अभिमान और अनदेखी एक अन्य रूप में बंगाल के राजनेताओं के रवैये से मेल खाती है।  
सच या झूठ तो अलग बात है, लेकिन बंगाली इस

तथ्य से भली भांति परिचित हैं कि एक अन्य पूर्ण मुख्यमंत्री ज्योति बसु ने ध्वाजारोहण के किसी भी कार्यक्रम में शामिल होने से इन्कार कर दिया था। कम्युनिस्टों ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को लेकर यह कठोर नारा दिया था कि “यह झूठा है।”  
गणतंत्र दिवस परेड या स्वतंत्रता दिवस के स्मरण (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

## डॉनल्ड ट्रम्प की 2024 के चुनाव में पुनः राष्ट्रपति बनने की संभावना नगण्य नहीं है

ट्रम्प स्वयं भी लगभग कह चुके हैं कि वे पुनः राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ेंगे 2024 में

—सुकुमार साह—  
—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—  
नई दिल्ली, 8 सितम्बर। वर्ष 2024 को आने दीर्घा दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र डॉनल्ड ट्रम्प की अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में वापसी देख सकता है और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी की लगातार तीसरी बार वापसी देख सकता है। लोकतंत्रों को वोटिंग के जरिए नेतृत्व परिवर्तन के लिए जाना जाता है। यदि ऐसा है तो डॉनल्ड ट्रम्प अमेरिका का सबसे बड़ा सार्वजनिक पद पुनः प्राप्त कर सकते हैं, हालांकि उन्हें जनवरी 2020 में समाप्त हुए अपने प्रथम राष्ट्रपति कार्यकाल में मनमाफिक प्रतिष्ठा नहीं मिल पायी थी।  
इसके विपरीत मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा एक सर्वमान्य पार्टी बनने की हर कोशिश कर रही है, बावजूद इसके कि बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक समुदायों के कथित ध्रुवीकरण और भाषा एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर समय-समय पर होने वाले हमलों को लेकर उसकी सरकार की व्यापक आलोचना है।  
बिखरा हुआ विपक्ष वर्ष 2024 में मोदी को चुनौती देने के लिए मुश्किल से एकजुट होने की कोशिश कर रहा है। कांग्रेस, जो कि पूर्ण रूप से अव्यवस्थित है, कयाकुमारी पर समय-समय पर होने अपनी “भारत जोड़ो” पदयात्रा से पार्टी को पुनर्जीवित करने के प्रयास कर रही है। अमेरिका में, ट्रम्प ने घोषणा की है

■ नवीनतम सर्वे के अनुसार, 63 प्रतिशत रिपब्लिकन्स (ट्रम्प की पार्टी को लोग) चाहते हैं कि, ट्रम्प देश की राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका रखें।  
■ परन्तु फिर भी, अभी केवल 39 प्रतिशत रिपब्लिकन पार्टी चाहती हैं कि, ट्रम्प स्वयं राष्ट्रपति बनें, जबकि बाकी 23 प्रतिशत चाहते हैं कि राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका रखते हुए ट्रम्प किसी और उम्मीदवार, जिसके विचार ट्रम्प से मेल खाते हैं, को समर्थन देकर राष्ट्रपति बनवायें।  
■ जहां तक वर्तमान राष्ट्रपति बाइडन को पुनः राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाने की बात है, उनकी पार्टी, डेमोक्रेटिक पार्टी में उनकी उम्र पर चिंता है। बाइडन 79 वर्ष के हो चुके हैं और वे अगर दोबारा चुनाव लड़ कर राष्ट्रपति बनें तो उनकी उम्र 82 वर्ष की होगी। साथ ही 2024 में क्या वे अपनी उम्र के कारण, दोबारा सत्ता में आने को तत्पर व आक्रामक, रिपब्लिकन पार्टी की चुनौती का उत्साह पूर्ण जवाब दे सकेंगे।

कि अगले राष्ट्रपति चुनाव में वह उम्मीदवार बनेंगे। वे इसमें जीतते हैं या नहीं यह अलग प्रश्न है। वे चाहे कुछ भी सोचें, हाल ही का एक सर्वेक्षण संकेत देता है कि अमेरिका के सिर्फ 30 प्रतिशत वोटर्स ही ट्रम्प को एक बड़े

### मजबूत अर्थव्यवस्था

—जाल खंबाता—  
—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—  
नई दिल्ली, 8 सितम्बर। भारत सरकार को उम्मीद है कि देश की अर्थव्यवस्था में इस वर्ष 7 प्रतिशत या उससे अधिक वृद्धि होगी। द न्यूयॉर्क टाइम्स की एक खबर कहती है कि यह वृद्धि वैश्विक आर्थिक वृद्धि के प्रोजेक्शन से दोगुनी से भी अधिक है। न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है कि अर्थव्यवस्था का यह तीव्र विस्तार

■ न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है कि, भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत है और महामारी के झटकों से उबर कर तेजी से आगे बढ़ रही है।

विपरीत परिस्थितियों में की गई उन कोशिशों को आंशिक रूप से परिलक्षित करता है, जब अर्थव्यवस्था वैश्विक महामारी के दौरान लगे गहरे झटके से घराशायी हो गई थी और इससे बाध्य होकर मजदूरों ने शहरों से पलायन कर दिया था। यह भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति को भी परिलक्षित करती है, जो वैश्विक ट्रेण्ड्स से आंशिक रूप से ही (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

## ‘इतना गुस्सा क्यों?’

ममता बनर्जी ने प्र.मंत्री मोदी को यह सवाल संबोधित किया

■ —डॉ. सतीश मिश्रा—  
—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—  
नई दिल्ली, 8 सितम्बर। भाजपा के नेतृत्व वाली प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार ने पहले बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को भारत यात्रा के दौरान प. बंगाल का मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को नहीं बुलाया, फिर दिल्ली में नेताजी सुभाषचंद्र बोस की प्रतिमा के उद्घाटन के लिए उन्हें एक आई.ए.एस. अफसर द्वारा हस्ताक्षरित निमंत्रण पत्र भेज दिया, इसे ममता बनर्जी के अपमान के रूप में देखा जा रहा है।  
बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, जो चार दिन भारत की यात्रा पर हैं, से मुलाकात के लिए नहीं बुलाने पर एतराज जताते हुए ममता बनर्जी ने कहा, “हसीना जी यहां हैं। मेरे उनसे व उनके परिवार से बहुत अच्छे संबंध हैं हम पूजा और ईद पर एक दूसरे को तोहफे देते हैं, वे मेरे लिए हिल्सा (मछली) व आम भिजवाती हैं। उन्हें मुझ से मिलने की इच्छा जताई थी। ऐसा पहली बार है जब बांग्लादेश की प्रधानमंत्री यहां हैं और बंगाल की उपेक्षा की गई है। हसीना जी मुझसे मिलना चाहती थीं मैं उनकी आभारी हूँ। मैंने समाचारों में देखा था। खैर ये अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं, रहने दीजिए। पर आप इतने गुस्सा क्यों हैं? इतना गुस्सा क्यों?”  
इसी के साथ उन्होंने कहा कि वे

दिल्ली में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की प्रतिमा के अनवरण कार्यक्रम में भाग नहीं लेंगी क्योंकि आमंत्रण उन्होंने कहा कि, उन्हें कल निमंत्रण मिला जिसमें एक सरकारी अफसर ने उन्हें कार्यक्रम की सूचना दी थी।  
बनर्जी बोली, “मुझे कल एक पत्र मिला जो शायद किसी अण्डर सैक्रेटरी ने लिखा था, जिसमें बताया गया था कि प्रधानमंत्री 7 बजे नेताजी की प्रतिमा का

अनवरण करेंगे आपको 6 बजे तक पहुंचना होगा। मानो मैं कोई उनकी नौकर या बंधुआ मजदूर हूँ। एक अण्डर सैक्रेटरी मुख्यमंत्री को कैसे लिख सकता है? संस्कृति मंत्री इतने बड़े कैसे बन गए।  
उन्होंने कहा, उनकी समझ खत्म हो गई है। इसलिए मैं यहां आई हूँ नेताजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर अपनी श्रद्धा प्रकट करने जो वे दिल्ली में करेंगे

मैंने वो बंगाल में कर दिया।  
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इंडिया गेट और सेंट्रल विस्टा तथा राज पथ, जिसका नाम कर्तव्य पथ हो गया है, के समीप नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की 28 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे।  
इससे पूर्व उन्होंने यह भी कहा था कि वे हैरान हैं कि भाजपा नीत केन्द्र सरकार उनकी शेख हसीना से मुलाकात (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

## कर्नाटक में भी भाषा विवाद गर्मायेगा?

हालांकि, तमिलनाडू “हिन्दी थोपने” के विरोध में दक्षिण भारत में सबसे अग्रणी है, पर कर्नाटक में भी यह आंदोलन सुलगता रहा है

—लक्ष्मण बेंकट कुची—  
—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—  
नई दिल्ली, 8 सितम्बर। दूरगामी असर की सम्भावना वाली एक घटना के अन्तर्गत, एक डिस्ट्रिक्ट कन्स्यूमर ग्रोवसेज रिड्रेसल फोरम ने भारतीय स्टेट बैंक को कन्नड़ भाषा में लिखे बैंक की “डिसऑनर” करने का दोषी ठहराया है, ज्ञातव्य है कि कन्नड़ कर्नाटक राज्य की भाषा है तथा यह बैंक कर्नाटक में ही था। धारवाड़ कन्स्यूमर फोरम ने बैंक को “सेवा की कमी” (डेंफिसिप्सरी ऑफ सर्विस) का दोषी ठहराते हुये, स्टेट बैंक पर 85,177रु का जुर्माना लगाया है।  
वेदिराजाचार्य इनामदार, जो अंग्रेजी के व्याख्याता हैं, ने 3 सितम्बर, 2020 को अपने बिजली के बिल के भुगतान के लिये हुबली इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कम्पनी लिमिटेड (एच.ई.एस.कॉम. अर्थात हैसकॉम)

■ हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा कन्नड़ भाषा में लिखे एक बैंक को पास नहीं करने से, सुगलती आग को हवा लग गयी है।  
■ उपभोक्ता कोर्ट ने इस कृत्य को बैंक की गलती मान कर बैंक पर पिच्यासी हजार रु. का फाइन लगाया।  
■ कन्नड़ भाषियों ने इस निर्णय का भारी जोश व उत्साह से स्वागत किया तथा यह भावना फैली कि, बैंक, पी.एस.यू. आदि कन्नड़ भाषी लोगों को अंग्रेजी व हिन्दी भाषी लोगों की तुलना में पूरा सम्मान नहीं देते। अतः इसका राजनीतिक इलाज होना चाहिये।  
■ अगर कन्नड़ भाषी लोगों के साथ दुर्व्यवहार की यह भावना और पकड़ गयी तो, भाषा विवाद कर्नाटक में भी जड़ पकड़ सकता है।

के नाम 6000रु का बैंक जारी किया था। बैंक हैसकॉम का खाता केनरा बैंक में है, इसलिये यह बैंक क्लिअरेंस के

लिये उत्तर कन्नड़ जिले के हलियाल कस्बे में स्थित एस.बी.आई. ब्रांच में (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

वासनिक को हटाया  
—जाल खंबाता—  
—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—  
नई दिल्ली, 8 सितम्बर। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने दिल्ली के पूर्व सांसद जय प्रकाश अग्रवाल को मध्यप्रदेश का नया ए.आई.सी.सी. प्रभारी नियुक्त किया है। वह मुकुल वासनिक का स्थान लेंगे।

■ कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मध्यप्रदेश के पार्टी प्रभारी का पद मुकुल वासनिक से लेकर पूर्व सांसद जे.पी. अग्रवाल को दे दिया।  
कांग्रेस के संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने बताया कि वासनिक ने अनुरोध किया था कि उन्हें मध्यप्रदेश की जिम्मेवारी से मुक्त किया जाए, ताकि वह संगठन के अन्य मसलों पर गौर कर सकें।  
उन्होंने कहा कि वासनिक ए.आई.सी.सी. महासचिव बने रहेंगे।

राष्ट्रीय व्यक्तिगत के रूप में देखा चाहते हैं।  
एक हालिया प्यु रिचर्स सर्वे से पता चलता है कि 63 प्रतिशत रिपब्लिकन्स का कहना है कि पूर्व राष्ट्रपति को राष्ट्रीय राजनीति में बड़ी भूमिका अदा करना जारी रखना चाहिए, जबकि सभी डेमोक्रेट्स और डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रति झुकाव रखने वाले 94 प्रतिशत लोगों का कहना है कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए।  
जो रिपब्लिकन्स कहते हैं कि ट्रम्प को एक बड़ा राष्ट्रीय व्यक्तित्व बने रहना चाहिए, उनका शेयर सितम्बर 2021 के 67 प्रतिशत से गिरकर अब 63 प्रतिशत पर आ गया है।  
(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

देता है कि अमेरिका के सिर्फ 30 प्रतिशत वोटर्स ही ट्रम्प को एक बड़े